

संख्या:-166/XIV-1/2016-5(19)/2010-टी0सी0

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून

दिनांक 15 फरवरी, 2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहकारी सहभागिता योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या:-7615/नियो0/सहभागिता/सामान्य/2015-16 दिनांक 16 दिसम्बर, 2015, वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या:-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 व पत्र संख्या-645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1136/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के पैरा-5 के अनुसार एवं शासनादेश संख्या-1379/XXVII(1)/2015 दिनांक 27 नवम्बर, 2015, शासनादेश संख्या-49/XXVII(1)/2016 दिनांक 25 जनवरी, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी सहभागिता योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दिये जाने वाले कृषि/कृष्येत्तर ऋणों के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी0पी0एल0 परिवारों, के कृषकों को अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किए जाने वाले ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि में से **रु0 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त दावों का निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त ही सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2016 तक ही सस्ते ऋण के सापेक्ष वार्षिक देयता के अनुरूप ब्याज अनुदान अनुमन्य होगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-400/XXVII (1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं 17 नवम्बर, 2015 का शब्दशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। योजना के नियोजन विभाग से कराये गए मूल्यांकन अध्ययन की संस्तुतियों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूपसे उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

कमशः

(2)

(4) धनराशि का योजनावार व्यय विवरण निबन्धक प्रत्येक माह बी0एम0-13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-13-सहकारी सहभागिता योजना-00-50-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग(अनुभाग-4) के अशासकीय संख्या-143(P)/XXVII(4)/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या:-166(1)/XIV-1/2016, तददिनांकित।

14. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
17. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
18. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
20. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
21. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।
22. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
23. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
24. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
25. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
26. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।